



भारत में वामपंथी उग्रवाद का परदाफाश

यह एडिटरियल 19/12/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित [“Grass-root democracy as a bulwark against Maoists”](#) लेख पर आधारित है। इसमें चर्चा की गई है कि यदि PESA को उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित किया जाए तो यह आदवासी लोगों को विकास कार्यक्रमों एवं सामाजिक न्याय के योजना-निर्माण एवं क्रियान्वयन में भागीदारी करने में सक्षम बना सकता है, साथ ही उनके अधिकारों और संसाधनों की रक्षा भी कर सकता है।

प्रलमिस के लिये:

[वामपंथी उग्रवाद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल \(CAPF\), केंद्रीय रज़िर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल \(BSF\), भारत-तबिबत सीमा पुलिस \(ITBP\), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना \(PMGSY\), वन धन विकास केंद्र, पंचायत \(अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार\) अधिनियम, 1996 \(PESA\)।](#)

मेन्स के लिये:

वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद के पीछे कारण, सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनका प्रभाव, आगे की राह।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जहाँ मुख्य ध्यान जनजाति/आदवासी मतों पर केंद्रित रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जो राज्य के कुल मतों में 34% की हस्तिसेदारी रखते हैं और इस क्षेत्र में सरकार के गठन के लिये उनका समर्थन पाना प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर में, वर्तमान में माओवादी विद्रोह की समस्या पाई जाती है जहाँ जनजातीय आबादी इस आंदोलन के लिये प्राथमिक आधार के रूप में कार्य करती है। [पाँचवी अनुसूची के क्षेत्रों \(Schedule Five areas\)](#) के रूप में वर्गीकृत इन माओवादी गढ़ों में चुनावों में लगातार हस्ति की घटनाएँ होती रही हैं जिनकी गंभीरता माओवादियों द्वारा चुनाव बहिष्कार के आव्हान से और बढ़ जाती है। इस वर्ष के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति नज़र आई जो इन क्षेत्रों में माओवादी विद्रोह द्वारा उत्पन्न जारी चुनौतियों को परलक्षित करती है।

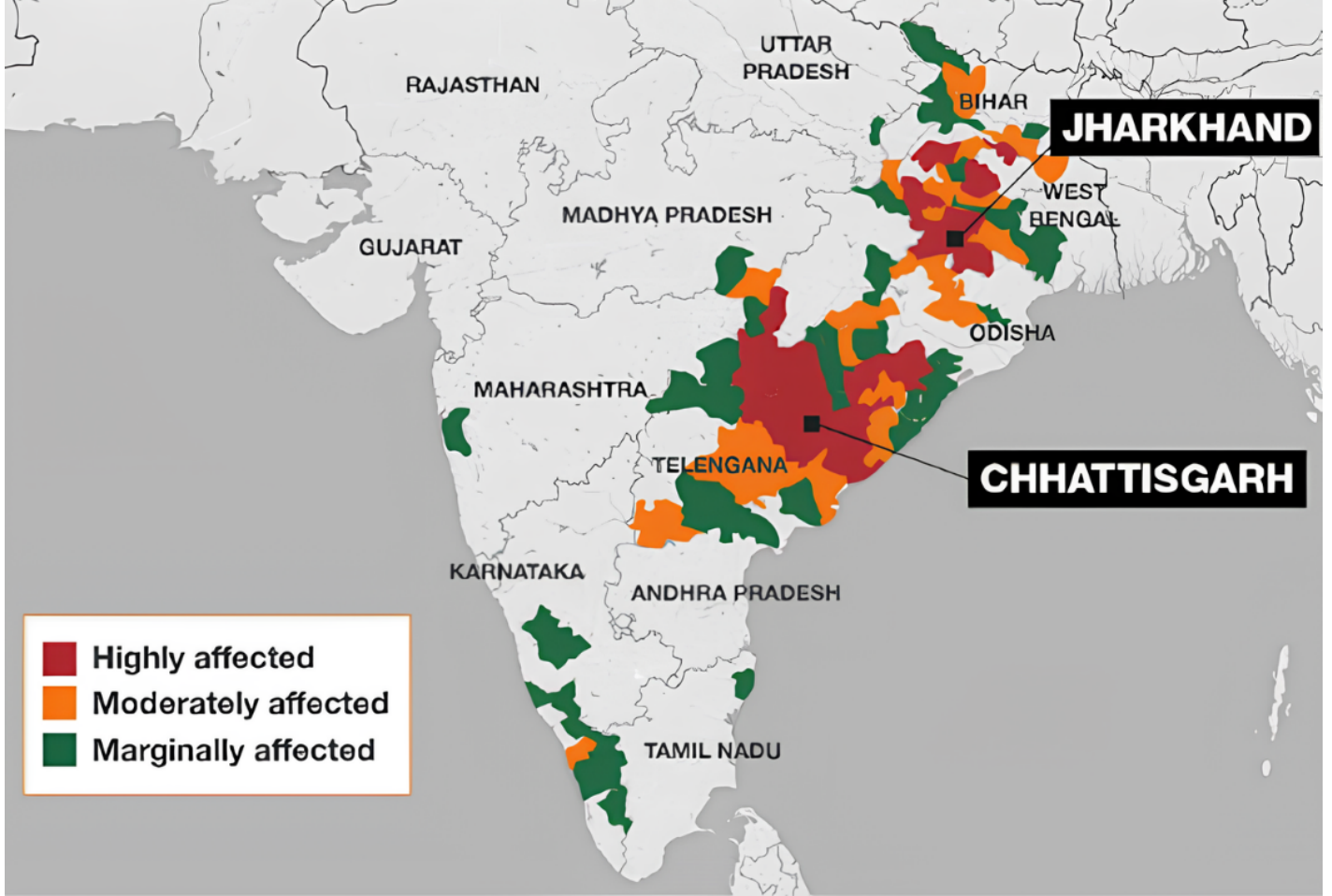
वामपंथी उग्रवाद:

परिचय:

- [वामपंथी उग्रवाद \(Left Wing Extremism- LWE\)](#), जसि वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से **महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की वकालत** करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये **सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या नज़ि संपत्ति** को नशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत **वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी (Naxalbari)** के उदय के साथ हुई।
- **भारत में LWE की उपस्थिति:** गृह मंत्रालय के अनुसार देश के 10 राज्यों के 90 ज़िले LWE से प्रभावित हैं, हालाँकि अलग-अलग ज़िलों में उनका स्तर भिन्न-भिन्न है।
 - ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।
 - इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार सर्वाधिक प्रभावित हैं, जहाँ वामपंथी समूहों की प्रबल उपस्थिति है और वे सुरक्षा बलों एवं नागरिकों पर लगातार हमले करते रहे हैं।

A map of India's Maoist conflict

A crackdown on Maoist rebels has led to a rise in the number of casualties in the country's tribal areas. Here are the regions that are most affected.



//

वामपंथी उग्रवाद के पीछे कौन-से प्रमुख कारण:

- **असमान विकास:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कई क्षेत्र देश के सबसे कम विकासित क्षेत्रों में शामिल हैं, जहाँ उच्च स्तर की गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, कुपोषण और सामाजिक अपवर्जन जैसी स्थितियाँ पाई जाती हैं।
 - वामपंथी उग्रवादी समूह समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय समुदाय की शिकायतों या असंतोष का फायदा उठाते हैं, जिन्हें राज्य और नज़ी अभिकर्ताओं द्वारा उनकी भूमि, वन और खनजि अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।
- **शासन की कमी:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र प्रभावी शासन, प्रशासन और सेवा वितरण की कमी से पीड़ित हैं। यहाँ सरकारी संस्थाएँ प्रायः अक्षम, भ्रष्ट या अनुपस्थित होती हैं, जिससे एक रकितता या नरिवात का नरिमाण होता है जिसे फरि LWE समूहों द्वारा भरा जाता है।
 - LWE समूह चुनाव, पंचायती कार्यकरण और विकास योजनाओं जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिये हसिा एवं भयादोहन का भी उपयोग करते हैं।
- **वैचारिक अपील:** LWE समूह उत्पीड़ित और शोषित वर्गों के हतियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करते हैं जो संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार करती है तथा सशस्त्र क्रांति की वकालत करती है।
 - वे चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग (Mao Zedong) की शक्तिओं और वर्ष 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेननिवादी) के नेतृत्व में उभरे नक्सलवादी विद्रोह से प्रेरणा ग्रहण करते हैं।
 - वामपंथी उग्रवाद से जुड़े कुछ समूहों के भारत और भारत के बाहर अन्य चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलनों से भी संबंध हैं।
- **वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वसि्थापन:** वैश्वीकरण के प्रभाव, जनिमें सांस्कृतिक परिवर्तन एवं वसि्थापन शामिल हैं, वसि्थापन और अलगाव की

भावना में योगदान कर सकते हैं।

- वामपंथी उग्रवादी आंदोलन उन व्यक्तियों को अस्मिता एवं उद्देश्य की एक भावना प्रदान कर सकते हैं जो इन वैश्विक शक्तियों द्वारा हाशिये की ओर धकेले जाना महसूस करते हैं।

सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये गए हैं?

■ सुरक्षा उपाय:

- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती:** सरकार ने उग्रवाद वरिधी अभियान चलाने और पुलिस उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में **CRPF, BSF और ITBP जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces- CAPFs)** की तैनाती की है।
- **राज्य पुलिस को सबल करना:** केंद्र सरकार राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया जानकारी संग्रहण में सुधार और उग्रवाद वरिधी रणनीति में कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये वित्तीय एवं लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करती है।
- **वर्षीय इकाइयों की स्थापना:** नक्सली नेताओं और कैंपों के वरिद्ध लक्षित अभियान चलाने के लिये 'कोबरा कमांडो' और 'ग्रेहाउंड' जैसी वर्षीय इकाइयाँ बनाई गई हैं।

■ विकास पहल:

- **एकीकृत विकास परियोजनाएँ:** सरकार ने LWE प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार, आजीविका के अवसर प्रदान करने और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये **एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (ITDP) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी विभिन्न योजनाएँ** शुरू की हैं।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने और नक्सली भर्ती के प्रती उनका भेद्यता को कम करने के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
- **स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना:** **वन धन विकास केंद्र** और मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं का लक्ष्य वन-आधारित गतिविधियों एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिये सतत आजीविका के अवसर पैदा करना है।

■ अधिकार और हकदारी सुनिश्चित करना:

- **भूमि अधिकार:** सरकार जनजातीय समुदायों के समक्ष वदियमान भूमि अलगाव (land alienation) की समस्या के समाधान के लिये भी कदम उठा रही है, जो नक्सली असंतोष का एक प्रमुख कारण रहा है।
- **वन अधिकार:** वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और सामुदायिक वन प्रबंधन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।
- **शिकायत नविवरण तंत्र:** सरकार ने स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये शिकायत नविवरण तंत्र स्थापित किये हैं।

■ अन्य उपाय:

- **सविकि एक्शन प्रोग्राम (CAP):** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न सविकि एक्शन कार्यक्रम के संचालन के लिये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वित्तीय अनुदान आवंटित किया जाता है।
- **आत्म-समर्पण और पुनर्वास नीति:** पुनर्वास पैकेज के तहत उच्च रैंक के LWE कैडरों के लिये 2.5 लाख रुपए और मध्यम/नचिली रैंक के कैडरों के लिये 1.5 लाख रुपए उनके नाम पर सावधि जमा के रूप में रखे जाते हैं जिन्हें अच्छा आचरण प्रकट करने पर 3 वर्ष पूरा होने के बाद निकाला जा सकता है।
 - उन्हें उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और तीन वर्षों के लिये 4000 रुपए प्रति माह की वृत्त प्रदान की जाती है।
- **'समाधान' सदिधांत:** वामपंथी उग्रवाद की समस्या का कोई रामबाण समाधान संभव नहीं है। इसके लिये अलग-अलग स्तरों पर अल्ट्रावधकि, मध्यम आवधकि और दीर्घावधकि नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। 'समाधान' (SAMADHAN) का पूर्ण रूप है:
 - S- स्मार्ट लीडरशिप
 - A- एग्रेसिव स्ट्रेटेजी
 - M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग
 - A- एक्शनेबल इंटेल्जिंस
 - D- डैशबोर्ड-बेसड KPIs (Key Performance Indicators) और KRAs (Key Result Areas)
 - H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी
 - A- एक्शन प्लान फॉर इच थिएटर
 - N- नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग
- **स्मार्ट पुलिस:** 'स्मार्ट' रणनीतिक प्रबंधन और वैकल्पिक प्रतिक्रिया रणनीति (SMART- Strategic Management & Alternative Response Tactics) का संक्षिप्त रूप है, जो पुलिस प्राधिकारों द्वारा डेटा-संचालित दृष्टिकोण के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।
 - स्मार्ट पुलिस का लक्ष्य सूचना-संपन्न नरिणयन एवं संसाधन आवंटन के लिये डेटा के विभिन्न स्रोतों—जैसे अपराध के आँकड़े, नागरिक प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया आदि का उपयोग कर पुलिस कार्य की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करना है।
 - स्मार्ट पुलिस में पुलिस प्रेषण के विकल्प भी शामिल हैं, जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट, टेलीफोन रिपोर्टिंग इकाइयाँ और फाल्स अलार्म में कमी लाना।

इन उपायों का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है?

- पछिले आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवादी हिसा के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक प्रसार में उल्लेखनीय गरिवट देखी गई है।

(2015)

Q. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिये? (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unmasking-left-wing-extremism-in-india>

